रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 5 मार्च, 2002/14 फाल्गुन, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 मार्च, 2002

संख्या 1-19/2002-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक

3318-राजपत्र/2002-5-3-2002—1,339. (4339) मूल्य : 1 रुपया ।

संख्यांक 1)" जो आज दिनांक 5 मार्च, 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2002 का विधेयक संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2002 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 2,19,50,28,668 रुपए की और राशि जारी करना।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियां जिनका योग 2,19,50,28,668 रुपए (दो सौ उन्नीस करोड़, पचास लाख, अठाइस हजार, छः सौ अडसठ रुपए) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 2001-2002 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा	(राजस्व)	1,69,80,000	2,00,000	1,71,80,000
2	राज्यपाल और मंत्रि-परिषद्	(राजस्व)	1,28,30,000	—	1,28,30,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	2,00,99,000	11,550	2,01,10,550
	और निर्वाचन	(पूंजी)	64,00,000	—	64,00,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	91,80,000	—	91,80,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व)	36,48,000	—	36,48,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	52,80,000	—	52,80,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	50,61,000	6,13,624	56,74,624
		(पूंजी)	80,50,000	—	80,50,000
8	शिक्षा	(राजस्व)	16,29,44,500	—	16,29,44,500
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व)	6,70,50,000	9,69,899	6,80,19,899
		(पूंजी)	1,01,20,000	24,92,458	1,26,12,458
10	लोक निर्माण-भवन	(राजस्व)	10,64,000	—	10,64,000
		(पूंजी)	28,37,000	—	28,37,000
11	कृषि	(राजस्व)	3,70,28,000	—	3,70,28,000
		(पूंजी)	3,52,67,000	—	3,52,67,000
12	उद्यान	(राजस्व)	9,23,96,000	—	9,23,96,000
		(पूंजी)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
13	सिचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	10,00,000	—	10,00,000
		(पूंजी)	18,00,000	—	18,00,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	5,84,93,000	48,519	5,85,41,519
		(पूंजी)	95,40,000	—	95,40,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व)	1,000	—	1,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	—	19,323	19,323
		(पूंजी	8,01,000	—	8,01,000

2		3		
		रुपये	रुपये	रुपये
सड़कें और पुल	(राजस्व)	44,00,000	—	44,00,000
	(पूंजी)	5,55,12,000	1,82,24,807	7,37,36,807
आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	10,47,50,000	78,159	10,48,28,159
	(पूजी)	—	2,81,245	2,81,245
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	1,66,81,000	—	1,66,81,000
ग्रामीण विकास	(राजस्व)	10,35,000	—	10,35,000
सहकारिता	(पूंजी)	2,42,36,000	—	2,42,36,000
खाद्य और भाण्डागारण	(राजस्व)	3,06,000	—	3,06,000
मुद्रण और लेखन सामग्री	(राजस्व)	3,96,00,000	23,557	3,96,23,557
सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	24,01,00,000	—	24,01,00,000
पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	1,51,80,000	—	1,51,80,000
	(पूंजी)	1,26,54,000	—	1,26,54,000
श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(पूंजी)	16,00,000	—	16,00,000
जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	12,85,32,000	3,10,000	12,88,42,000
	(पूंजी)	72,09,58,000	11,09,152	72,20,67,152
वित्त	(राजस्व)	9,04,49,665	1,85,28,010	10,89,77,675
	(पूंजी)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	1,14,26,000	—	1,14,26,000
	(पूंजी)	80,00,000	—	80,00,000
जनजातीय विकास	(राजस्व)	6,75,38,200	—	6,75,38,200
	(पूंजी)	12,91,000	—	12,91,000
कुल जोड़		2,15,21,18,365	4,29,10,303	2,19,50,28,668
	(राजस्व)	1,21,30,52,365	2,08,02,641	1,23,38,55,006
	(पूंजी)	93,90,66,000	2,21,07,662	96,11,73,662

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
दिनांक : 4 मार्च, 2002.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, नस्ति संख्या फिन0 ए0 सी0 (2)-18/2001]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 की विषय वस्तु के बारे में, संचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002

31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तिय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
दिनांक 4 मार्च, 2002.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2002.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2002

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2002.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2002.

Issue of a further sum of Rs. 2, 19,50,28,668 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2001-2002.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 2,19,50,28,668/- (Two hundred nineteen crore, fifty lakh, twenty eight thousand, six hundred and sixty eight) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2001-2002 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section (2) of this Act.

THE SCHEDULE

(*see* sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
Demand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha	(Revenue)	1,69,80,000	2,00,000	1,71,80,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	1,28,30,000	—	1,28,30,000
3	Administration of Justice and Election	(Revenue)	2, 00,99.000	11,550	2,01,10,550
		(Capital)	64,00,000	—	64,00,000
4	General Administration	(Revenue)	91,80,000	—	91,80,000
5	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	36,48,000	—	36,48,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	52,80,000	—	52,80,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	50,61,000	6,13,624	56,74,624
		(Capital)	80,50,000	—	80,50,000
8	Education	(Revenue)	16,29,44,500	—	16,29,44,500
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	6,70,50,000	9,69,899	6,80,19,899
		(Capital)	1,01,20,000	24,92,458	1,26,12,458
10	Public Works-Building	(Revenue)	10,64,000	—	10,64,000
		(Capital)	28,37,000	—	28,37,000
11	Agriculture	(Revenue)	3,70,28,000	—	3,70,28,000
		(Capital)	3,52,67,000	—	3,52,67,000
12	Horticulture	(Revenue)	9,23,96,000	—	9,23,96,000
		(Capital)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
13	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	10,00,000	—	10,00,000
		(Capital)	18,00,000	—	18,00,000
14	Animal Husbandry and Diary Development and Fisheries	(Revenue)	5,84,93,000	48,519	5,85,41,519
		(Capital)	95,40,000	—	95,40,000
15	Planning and Backword area Sub-Plan	(Revenue)	1,000	—	1,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	—	19,323	19,323
		(Capital)	8,01,000	—	8,01,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	44,00,000	—	44,00,000
		(Capital)	5,55,12,000	1,82,24,807	7,37,36,807
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	10,47,50,000	78,159	10,48,28,159
		(Capital)	—	2,81,245	2,81,245
19	Social Security and Welfare (including Nutrition)	(Revenue) (Capital)	1,66,81,000	—	1,66,81,000

1	2		3		
			Rs	Rs.	Rs.
20	Rural Development	(Revenue)	10,35,000	-	10,35,000
21	Co-operation	(Capital)	2,42,36,000	-	2,42,36,000
22	Food and Ware-housing	(Revenue)	3,06,000	—	3,06,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	3,96,00,000	23,557	3,96,23,557
25	Road, and Water Transport	(Revenue)	24,01,00,000	—	24,01,00,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	1,51,80,000	—	1,51,80,000
		(Capital)	1,26,54,000	—	1,26,54,000
27	Labour Employment And Training	(Capital)	16,00,000	—	16,00,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	12,85,32,000	3,10,000	12,88,42,000
		(Capital)	72,09,58,000	11,09,152	72,20,67,152
29	Finance	(Revenue)	9,04,49,665	1,85,28,010	10,89,77,675
		(Capital)	2,00,00,000	—	2,00,00,000
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	1,14,26,000	—	1,14,26,000
		(Capital)	80,00,000	—	80,00,000
31	Tribal Development	(Revenue)	6,75,38,200	—	6,75,38,200
		(Capital)	12,91,000	—	12,91,000
	Grand Total		2,15,21,18,365	4,29,10,303	2,19,50,28,668
		(Revenue)	1,21,30,52,365	2,08,02,641	1,23,38,55,006
		(Capital)	93,90,65,000	2,21,07,662	96,11,73,662

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislature Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2001-2002.

PREM KUMAR DHUMAL.
Chief Minister.

SHIMLA :
The 4th March, 2002.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[FINANCE DEPARTMENT FILE NO. FIN. A.C. (2)-18/2001]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2002 recommends, under Article 207 of the Constitution of India the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2002

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 2002.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The 4th March, 2002.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित